



शिक्षकों के अनुभव पर योगी सरकार का जोर

टीईटी अनिवार्यता के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्देश



लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह सेवारत

शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य बनाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के शिक्षक अनुभवी हैं और उन्हें सर कार द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया गया है। ऐसे में

उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा कि योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। पिछले पाँच दिनों में, उत्तर प्रदेश में दो शिक्षकों—जो चालीस और पचास के दशक के अंत में थे—ने आत्महत्या कर ली है। कथित तौर पर वे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा अनिवार्य की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने के

दबाव का सामना नहीं कर पाए। उनके परिवारों का आरोप है कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की तैयारी को लेकर तनाव में थे। 1 सितंबर, 2025 को, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फैसला सुनाया कि पाँच साल से अधिक की सेवा शेष रहने वाले सभी सरकारी स्कूल शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करना होगा अन्यथा उन्हें अनिवार्य से सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र का सामना करना पड़ेगा। यह आदेश तमिलानाडु और महाराष्ट्र में शिक्षकों की नियुक्तियों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया था, लेकिन इसका अखिल भारतीय प्रभाव है, जिससे लगभग 10 लाख शिक्षक प्रभावित हैं—जिनमें से लगभग दो लाख अकेले उत्तर प्रदेश में हैं।

दून में भारी बारिश का रेड अलर्ट, सभी स्कूल बंद, प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम



देहरादून (एजेंसी)।

राजधानी दून में भारी बारिश के बीच सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए। वहीं सीएम धामी प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग और एनडीएमपी के अलर्ट के बाद देहरादून जिले में आज भारी से बहुत भारी बारिश, गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई। इसके चलते जिला प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। देर रात राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी तबाही मची है।

इसे देखते हुए दून में सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से सभी शासकीय, गैर शासकीय और निजी स्कूलों सहित आंगनबाड़ी केंद्रों में आज अवकाश घोषित कर दिया है। हालांकि यह आदेश केवल छात्रों के लिए होगा, जबकि शिक्षक और कर्मचारी सामान्य रूप से स्कूल आएंगे। प्रशासन ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ घटना की जानकारी मिलते ही सीएम धामी मोर्चे पर उट गए। प्रभावित क्षेत्रों को स्थलीय निरक्षण कर रहे हैं।

मोदी सरकार का नशा मुक्त भारत का संकल्प

2047 तक खत्म होगा खतरा:शाह

नई दिल्ली (एजेंसी)।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश से सभी प्रकार

समेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ



के नशीले पदार्थों का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक द्रव्य निरोधक कार्यबल (एएनडीएफ) के प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय

कार्रवाई के पैमाने में बदलाव किया जाए ताकि आने वाले दिनों में और अधिक सफलताएं मिलें। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने 2047 में एक महान भारत के निर्माण की संकल्पना प्रस्तुत की। एक ऐसा भारत जो पूर्णतः विकसित होगा।

अगर हमें ऐसा भारत बनाना है, तो अपनी युवा पीढ़ी को नशे से बचाना बेहद जरूरी है। क्योंकि किसी भी महान राष्ट्र की संकल्पना, उसकी नींव उस देश की युवा पीढ़ी होती है। अगर हमारी आने वाली पीढ़ियाँ खोखली हो जाएंगी, तो देश भटक जाएगा... दुर्भाग्य से, वे दोनों क्षेत्र जहाँ से दुनिया भर में नशे की आपूर्ति होती है, हमारे नजदीक ही हैं... इसलिए यही समय है कि हम इसके खिलाफ मजबूती से लड़ें। शाह ने कहा कि तीन तरह के कार्टेल होते हैं, एक वो कार्टेल जो देश के सभी एंटी पॉइंट्स पर काम करता है, दूसरा वो कार्टेल जो एंटी पॉइंट से राज्य तक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्टेल है और तीसरा वो कार्टेल जो राज्यों में पान की दुकान या गली के नुककड़ पर ड्रग्स बेचने तक काम करता है। इन तीनों

तरह के कार्टेल्स पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। मेरा मानना ? है कि ऐसा तभी हो सकता है जब यहां बैठे लोग तय कर लें कि ये लड़ाई हमारी लड़ाई है। अमित शाह ने कहा कि भगोड़ों का निर्वासन और प्रत्यर्पण, ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब समय आ गया है कि जो लोग विदेश में बैठकर यहाँ नशे का कारोबार कर रहे हैं, उन्हें हमारे कानून के दायरे में लाया जाए। सीबीआई ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी एएंडटीएफ अध्यक्षों से अनुरोध करता हूँ कि वे सीबीआई निदेशक से संपर्क करें और प्रत्यर्पण के लिए एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करें, जो न केवल नशे, आतंकवाद, गिरोहों, बल्कि हर चीज के लिए उपयोगी हो।

अदालत की फटकार के बाद 140 करोड़ रुपये की लंबित

इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी का भुगतान करेगी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार जल्द ही करीब 140 करोड़ रुपये की लंबित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सब्सिडी का भुगतान शुरू करेगी।

अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने सोमवार को कहा कि विभाग पिछले दो वर्षों से लंबित आवेदनों के निपटान के लिए इनका सत्यापन करेगा। एक अधिकारी के अनुसार, सरकार लंबित बकाया राशि के भुगतान के लिए एक पोर्टल भी तैयार कर रही है। इससे पहले दिल्ली उच्च



ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी का वितरण करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार

राव गेडला की पीठ ने कहा था कि सरकार इस तथ्य की आड़ में नहीं छिप सकती कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 में राशि देने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि आदेश का पालन किया जाएगा और विभाग ने पात्र लाभार्थियों की पहचान शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह देरी पिछले साल आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण हुई थी।

धर्मांतरण कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से जवाब मांगा, छह हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कई राज्यों से उनके धर्मांतरण रोधी कानूनों पर जवाब मांगा है। कोर्ट में दायर याचिकाओं में इन कानूनों की वैधता को चुनौती दी गई है और उन पर रोक लगाने की मांग की गई है। चौफ जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने साफ किया कि राज्यों के जवाब आने के बाद ही इन कानूनों पर रोक लगाने की अर्जी पर विचार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं को इसके

बाद दो हफ्ते का समय दिया गया है ताकि वे राज्यों की दलीलों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर सकें। इस मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पक्ष के वरिष्ठ वकील सी. यू. सिंह को याचिका संशोधित करने की भी अनुमति दी है, ताकि उत्तर प्रदेश जैसे



दरज कर सकें। इस मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पक्ष के वरिष्ठ वकील सी. यू. सिंह को याचिका संशोधित करने की भी अनुमति दी है, ताकि उत्तर प्रदेश जैसे

मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी। नीतीश ने कहा कि साथ ही 02 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण को 60 मासिक किस्तों (05 वर्ष) में वापस करने का प्रावधान था।

'भाजपा का ढोंग उजागर हो गया'

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे

मुंबई (एजेंसी)। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने से भाजपा की देशभक्ति का ढोंग उजागर हो गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश को इसमें भाग न लेकर दृढ़ता दिखानी चाहिए थी। भारत ने रविवार को खेले गए मैच में पाकिस्तान को सात विकेट से हरा दिया। हालांकि पहलगाम आतंकी



हमले के चलते सोशल मीडिया पर इस मैच का बहिष्कार करने की मांग उठ रही थी। पाकिस्तान से मैच खेलने को लेकर बीसीसीआई की भी आलोचना हो रही है। ठाकरे बोले- पाकिस्तान के साथ न खेलकर दृढ़ता दिखानी चाहिए थी

ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'भाजपा का ढोंग उजागर हो गया है। भारत न खेलकर दृढ़ता दिखानी चाहिए थी।' ठाकरे ने कहा कि अब यह साफ है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कई देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के बावजूद भारत को देशों से समर्थन क्यों नहीं मिला। ठाकरे ने कहा, 'जब हमने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है, तो दुनिया आपसे सवाल पूछेगी। आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं या

बिहार के छात्रों की मौज! नीतीश सरकार ने शिक्षा ऋण से हटाया ब्याज का बोझ

बिहार (एजेंसी)। चुनावी साल से पहले छात्रों को बड़ी राहत देते हुए, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने घोषणा की है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी साझा की और इसे इच्छुक छात्रों पर वित्तीय बोझ कम करने वाला कदम बताया। नीतीश ने एक्स पर लिखा कि बिहार में 07 निश्चय योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण

छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए 02 अक्टूबर 2016 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 04 लाख रुपए का शिक्षा ऋण सामान्य आवेदक को 04 प्रतिशत ब्याज दर पर तथा महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेन्डर

आवेदक को मात्र 01 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी। नीतीश ने कहा कि साथ ही 02 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण को 60 मासिक किस्तों (05 वर्ष) में वापस करने का प्रावधान था।

महाप्रबन्धक नरेश पाल सिंह ने 11 रेल कर्मचारियों को किया पुरस्कृत

नई दिल्ली : महाप्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, नरेश पाल सिंह द्वारा प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी, जे.सी.एस. बोरा एवं उत्तर मध्य रेलवे के विभागाध्यक्षों की उपस्थिति में संरक्षा के प्रति किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए झाँसी, आगरा एवं प्रयागराज मण्डलों से अगस्त 2025 माह के लिए चयनित कुल 11 रेल कर्मचारियों को संरक्षा पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कृत कर्मचारियों में काली चरण, ट्रैक मेन्टेनर -क़र, बांदा, झाँसी मण्डल विक्रान्त बाबू राणा, कीमैन, कोसी कलां, आगरा मण्डल अंशुमान सिंह, प्वाइण्टस मैन, पनकीधाम/प्रयागराज मण्डल श्यामू पटेल, प्वाइण्टसमैन, प्रयागराज छिवकी/ प्रयागराज मण्डल भूरी सिंह, प्वाइण्टसमैन, हेतमपुर/ झाँसी मण्डल धरमपाल



किशन, वरि. ट्रेन मैनेजर-गुड्डा/ ईदगाह/ आगरा मण्डल दीपक

कुमार सुम्बरूई, लोको पायलट, प्रयागराज छिवकी/प्रयागराज

प्रयागराज मण्डल अमर सिंह, लोको पायलट गुड्डा, आगरा कैण्ट/

आगरा मण्डल शामिल हैं। अमर सिंह, लोको पायलट गुड्डा, आगरा

गुड्डा, आगरा कैण्ट/आगरा मण्डल को संयुक्त रूप से माह का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमर सिंह, लोको पायलट, मालगाड़ी, आगरा कैण्ट/आगरा मण्डल एवं रजनी कान्त, सहायक लोको पायलट, आगरा कैण्ट/आगरा मण्डल ने 24 जुलाई को गाड़ी सं. ICDT Goods पर कार्य के दौरान तुगलकाबाद-आगरा कैंट खण्ड में छाता-अझई स्टेशनों के मध्य अझई यार्ड में प्रवेश करते समय अचानक जर्क का अनुभव किया।कू द्वारा तुरंत गाड़ी को खड़ा किया तथा जर्क लगने वाले स्थान की जाँच करने पर रेल फ्रैक्चर पाया गया। इसकी सूचना सर्व सम्बंधित को दी। इस प्रकार इनकी सजगता एवं सतर्कता से एक संभावित रेल दुर्घटना को रोका गया।

भारतीय रेल में पहली बार प्राचार्य सम्मेलन

गोरखपुर: भारतीय रेल ने अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण को बेहतर और

कर्मचारियों को शुरूआती कोर्स और कार्यरत स्टाफ को समय-समय पर रीफ्रेशर ट्रेनिंग दी



आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसी कड़ी में पहली बार मल्टी डिजिटलिनरी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स (टैउेक) के प्राचार्यों का सम्मेलन ट्रैफिक निदेशालय के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। वर्तमान में भारतीय रेल के कुल 14 टैउेकसंस्थान फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण देते हैं। यहाँ नए भर्ती

जाती है। सम्मेलन में प्रमुख चर्चा केस स्टडीज के उपयोग पर हुई, जिनके माध्यम से ट्रेन संचालन और सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को बेहतर तरीके से समझाया जा सके। साथ ही प्रशिक्षण को अधिक संवादात्मक और रोचक बनाने के लिए सिमुलेटर के उपयोग को बढ़ाने पर विचार किया गया। प्रशिक्षण को

खलीलाबाद स्टेशन पर स्वच्छ दिखता रेलवे प्लेटफार्म

गोरखपुर, ː भारतीय रेल पर मनाये जा रहे स्वच्छता अभियान के



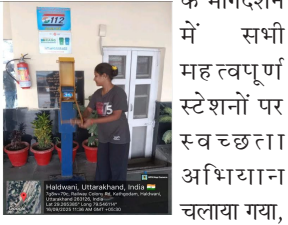
द्वितीय चरण के अन्तर्गत 16 सितम्बर, 2025 को पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ, वाराणसी एवं इज्जतनगर मंडलों पर स्वच्छता सम्बन्धी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह अभियान रेलवे के सभी क्षेत्रों जैसे-स्टेशनों, ट्रेनों, स्टेशन परिसरों, कॉलोनियों, कार्यालयों, डिपो एवं कारखानों आदि में स्वच्छता के प्रति हमारे प्रयासों को सार्थक करेगा, साथ ही रेल कर्मियों एवं यात्रियों के बीच जागरूकता को भी बढ़ावा देगा। 16 सितम्बर, 2025 को लखनऊ मंडल

पर मंडल रेल प्रबन्धक श्री गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन में सभी प्रमुख



स्टेशनों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके अन्तर्गत लखनऊ जं० एवं गोरखपुर स्टेशनों पर डस्टबिन की धुलाई तथा रेलवे ट्रैक के किनारों की सफाई की गयी। ऐशबाग, गोण्डा, बस्ती, खलीलाबाद स्टेशनों पर कार्यालयों, स्टेशन परिसर, प्लेटफार्मों पर गहन सफाई की गयी एवं यात्रियों को स्वच्छता बनाये रखने के लिये जागरूक किया गया। बंदरियाबाग एवं बादशाहनगर रेलवे कालोनी में स्वच्छता अभियान चलाकर रेलकर्मियों को स्वच्छता के प्रति

जागरूक किया गया। वाराणसी मंडल पर मंडल रेल प्रबन्धक श्री आशीष जैन



के मार्गदर्शन में सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके अन्तर्गत स्टेशनों पर कार्यरत अनुबन्ध कर्मचारियों एवं रेलकर्मियों के साथ स्वच्छता सम्बन्धित नारों, पोस्टर एवं बैनर के माध्यम से एक सार्वजनिक जागरूकता रैली निकाली गई। स्टेशनों पर बोटल क्रशर मशीन का उपयोग कर यात्रियों और कर्मचारियों को जागरूक किया गया। अभियान के दौरान स्टेशन पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वाटर हाइड्रेन्ट पाइप एवं वाटर बूथ का निरीक्षण किया गया। कचरे के पृथक्कीकरण हेतु स्टेशन पर अलग-अलग रंगों के डस्टबिन का प्रावधान

किया गया तथा स्टेशन परिसर की सफाई की गई। यात्रियों को स्टेशनों एवं ट्रेनों में स्वच्छता बनाये रखने हेतु जागरूक किया गया। इज्जतनगर मंडल पर मंडल रेल प्रबन्धक सुश्री वीणा सिन्हा के मार्गदर्शन में इज्जतनगर मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके अन्तर्गत काठगोदाम, हल्द्वानी, रूद्रपुर स्टेशनों पर बोटल क्रशर मशीन के उपयोग के बारे में यात्रियों को जागरूक किया गया। स्टेशनों पर उपलब्ध डस्टबिन की सफाई एवं धुलाई की गई तथा रेलवे ट्रैक के किनारों की सफाई की गयी। कासगंज रेलवे स्टेशन पर कार्यालयों एवं प्रतीक्षालय तथा स्टेशन परिसर की गहन सफाई की गयी। यात्रियों को स्टेशनों एवं ट्रेनों में स्वच्छता बनाये रखने के लिये जागरूक किया गया।

अमृतसर से 02.50 बजे छूटकर छैहरटा 03.20 बजे पहुँचेगी

गोरखपुर: रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु 14628/14627 छैहरटा-सहरसा-छैहरटा नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस का निर्यात संचलन छैहरटा से 20 सितम्बर,2025 से प्रत्येक शनिवार को तथा सहरसा से 22 सितम्बर,2025 से प्रत्येक सोमवार को निम्नवत किया जायेगा, जिसका शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 15 सितम्बर, 2025 सोमवार को 05531 सहरसा-छैहरटा उद्घाटन विशेष गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर किया गया था। यह रैर-वातानुकूलित श्रेणी की प्रीमियम ट्रेन है। इस गाड़ी में मेा बाइल चाँजिंग पोर्ट, आरामदायक सफर के लिये एयर प्रिंश बाँटी, रेडियम फ्लोर स्टिप्टम, स्वच्छ दिव्यांगजन-अनुकूल प्रसाधन, सेप्टी के लिये फायर डिटेक्शन, टॉक-बैक यूनिट, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था सहित उन्नत

यात्रा सुविधाये उपलब्ध हैं। 14628 छैहरटा-सहरसा साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस 20 सितम्बर, 2025 से प्रत्येक शनिवार को छैहरटा से 22.20 बजे प्रस्थान कर अमृतसर से 22.55 बजे, ब्यास से 23.25 बजे, दूसरे दिन जलंधर सिटी से 00.10 बजे, फगवाड़ा से 00.30 बजे, ढंङरग कलां से 01.30 बजे, सरहिन्द से 02.18 बजे, राजपुर से 02.40 बजे, अम्बाला कैण्ट से 03.35 बजे, यमुनानगर जगाधरी से 04.08 बजे, सहरानपुर से 05.10 बजे, रूङ्ढरी से 05.54 बजे, मुगदाबाद से 09.25 बजे, चन्दीसी से 10.42 बजे, सीतापुर से 16.40 बजे, बुङ्दल से 18.20 बजे, गोण्डा से 19.25 बजे, मनकापुर से 19.51 बजे, बस्ती से 20.40 बजे, खलीलाबाद से 21.07 बजे, गोरखपुर से 22.25 बजे, कप्तानगंज से 23.15 बजे, सिसवा बाजार से 23.42

बजे, तीसरे दिन नरकटियागंज से 02.00 बजे, सिकटा से 02.32 बजे, रक्सौल से 02.50 बजे, सीतामढ़ी से 04.33 बजे, शीशो से 05.40 बजे, सकरी से 06.35 बजे, झंझारपुर से 07.05 बजे, निर्मली से 07.40 बजे, सगगढ़ से 08.15 बजे तथा सुपौल से 08.47 बजे छूटकर सहरसा 10.00 बजे पहुँचेगी। वापसी यात्रा में 14627 सहरसा-छैहरटा साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस 22 सितम्बर, 2025 से प्रत्येक सोमवार को सहरसा से 13.00 बजे प्रस्थान कर सुपौल से 13.35 बजे, सरायगढ़ से 14.25 बजे, निर्मली से 14.45 बजे, झंझारपुर से 15.30 बजे, सकरी से 16.22 बजे, शिशो से 17.10 बजे, सीतामढ़ी से 19.05 बजे, रक्सौल से 22.30 बजे, सिकटा से 23.02 बजे, दूसरे दिन नरकटियागंज से 00.30

बजे, सिसवा बाजार से 02.17 बजे, कप्तानगंज से 02.45 बजे, गोरखपुर से 04.05 बजे, खलीलाबाद से 04.56 बजे, बस्ती से 05.22 बजे, मनकापुर से 06.17 बजे, गोंडा से 07.05 बजे, बुङ्दवल से 08.12 बजे, सीतापुर जं. से 10.45 बजे, चन्दीसी से 15.10 बजे, मुरादाबाद से 16.40 बजे, रूङ्ढी की से 19.29 बजे, सहरानपुर से 20.45 बजे, यमुनानगर जगाधरी से 21.14 बजे, अम्बाला कैण्ट से 22.20 बजे, राजपुर से 22.44 बजे, सरहिन्द से 23.06 बजे, तीसरे दिन ढंङरी कलां से 00.03 बजे, फगवाड़ा से 00.50 बजे, जलंधर सिटी से 01.25 बजे, ब्यास से 01.58 बजे तथा अमृतसर से 02.50 बजे छूटकर छैहरटा 03.20 बजे पहुँचेगी।

संक्षिप्त खबरें

मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक 18 को

बस्ती। मंडलायुक्त अखिलेश सिंह का अध्यक्षता में विकास कार्यों की मासिक मंडलीय समीक्षा बैठक 18 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से आयुक्त सभागार में होगी। यह जानकारी संयुक्त विकास आयुक्त कमला कान्त पांडेय ने दी। उन्होंने बताया कि बैठक में मंडल के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होकर अद्यतन प्रगति विवरण प्रस्तुत करेंगे

लो वोल्टेज से भिरिया बाजार के लोग त्रस्त

बस्ती। भानपुर उपकेंद्र से जुड़े भिरिया बाजार के उपभोक्ता लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर इसका असर पड़ रहा है। ग्रामीणों व दुकानदारों का कहना है कि वोल्टेज इतना कम रहता है कि पंखे, कूलर और फ्रिज चलना तो दूर, समय से पहले खराब हो जाते हैं। सबसे अधिक परेशानी कारोबारियों को हो रही है। पर्याप्त बिजली न मिलने से कारोबार ठप पड़ने लगा है। स्थानीय निवासी राजू, गोमती, राजेश, राजकुमार चौरसिया, सत्य प्रकाश चौधरी और अपूर्व सिंह ने बताया कि लो वोल्टेज ने उनकी दुकानदारी पर सीधा असर डाला है। उनका कहना है कि समस्या का स्थायी समाधान तभी होगा जब स्थानीय ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाए।

गन्ना सट्टा प्रदर्शन मेले में बारिश से खलल

बस्ती। सहकारी गन्ना विकास समिति गौर परिसर में सोमवार से दस दिवसीय गन्ना सट्टा प्रदर्शन मेले की शुरुआत हुई। बारिश के कारण पहले दिन मेले में केवल 44 किसान पहुंचे। समिति अध्यक्ष अरविंद सिंह ने शुभारंभ किया। कहा कि गन्ना आयुक्त के निर्देश पर यह आयोजन किया गया है। सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य ग्राहियों को सुधारना है। उन्होंने कहा कि मेले में चीनी मिल बंधनान और समिति के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। किसान सर्वे, पेड़ी-पौधा, आधार कार्ड, खाता नंबर, मोबाइल नंबर आदि में सुधार करा सकते हैं। सचिव ने बताया कि 25 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में किसानों को सुधार का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इसके बाद यदि किसी किसान की जानकारी में त्रुटि रह जाती है, तो भविष्य में सुधार संभव नहीं होगा। उन्होंने समिति क्षेत्र के सभी किसानों से अपील की कि समय रहते अपनी सूची की जांच अवश्य करा लें।

अपने ही घर में नकाब लगाकर मचाया चोर चोर का शोर

बस्ती। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के बहेरिया गांव में सोमवार को देर रात अजीबोगरीब घटना सामने आई। गांव के सोनू कुमार ने खुद ही अपने घर की दीवार में सेंध काटी और अनाज समेत अन्य सामान छिपा दिया। इसके बाद उसने चोर-चोर का शोर मचा दिया। शोर सुनकर ग्रामीण जुटे और पुलिस को सूचना दी। जांच में पुलिस ने चोरी का सामान घर के आसपास बरामद कर लिया। सेंध काटने में प्रयुक्त सब्बल भी बरामद हुआ। सीओ सिटी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि यह घटना पूरी तरह फर्जी निकली। सोनू ने मनगढ़ंत तरीके से नकबजनी की कहानी गढ़ी थी। आरोपी के खिलाफ अफवाह फैलाने और झूठी सूचना देने के आरोप में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

जिला स्तरीय चयन-ट्रायल में खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

बस्ती। शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में सोमवार को जिम्नार्स्टिक सीनियर पुरुष और सीनियर महिला वर्ग खिलाड़ियों का चयन-ट्रायल सुबह 11 बजे से किया गया। चर्चानि खिलाड़ी मंडल स्तरीय चयन-ट्रायल में भाग लेंगे। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि प्रयागराज में 25 से 26 सितंबर तक प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता होगी, जिसमें बस्ती की दोनों टीमें प्रतिभाग करेंगी। इसके अलावा कुशी सीनियर पुरुष और सब जूनियर बालक प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन-ट्रायल जिले स्तर का किया गया। यह प्रतियोगिता 27 से 29 सितंबर गोरखपुर और चार से छह अक्तूबर तक आगरा में होगी। चर्चानित खिलाड़ी मंडल स्तरीय चयन-ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा बॉक्सिंग सीनियर पुरुष वर्ग खिलाड़ियों का जिला स्तरीय चयन-ट्रायल हुआ।

शोरूम कर्मचारी की बाइक चोरी

बस्ती। नगर थाना क्षेत्र के गोटवा बाजार में स्थित ट्रक सर्विस सेंटर में कार्यरत कर्मचारी की बाइक चोरी हो गई। पीड़ित ने नगर पुलिस से शिकायत की है। पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़ित दीपक यादव निवासी चित्रा थाना गौर ने बताया कि वह शोरूम के सर्विस विभाग में वार्टी सहायक पद पर कार्यरत है। 13 सितंबर शाम को घर जाने के लिए बाहर आया तो बाइक गायब मिली। काफी खोजबीन के बाद भी पता न चलने पर उसने चोरी की आशंका जताई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

बस्ती जिला स्तरीय विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह कल

बस्ती। अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में बस्ती जिला स्तरीय विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन 17 सितंबर को 10 बजे से किया गया है। इसमें कक्षा 10, 11 और 12वीं तथा स्नातक छात्र-छात्राओं सिमेत अन्य मेधावियों को सम्मानित किया जाएगा और कैरियर संबंधित टिप्स दिए जाएंगे। कार्यक्रम में राकेश यादव शामिल होंगे। बताया गया कि एप के जरिये निशुल्क शिक्षा दी जाएगी।

डीएम से की मैराथन मार्ग सुधारने की मांग

बस्ती। नेशनल ए एसोसिएशन ऑफ ग्रुथ के अध्यक्ष भावेष पांडेय ने सोमवार को जिलाधिकारी से मुलाकात कर कंपनीबाग चौराहे और शास्त्री चौक (तिरंगा चौराहा) से संबंधित समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। कहा कि कंपनीबाग चौराहे पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण मार्ग अखंडस्थित है। 119 अक्तूबर को 14वीं बस्ती मैराथन में हजारों धावक इस मार्ग से गुजरेंगे। यातायात और सुरक्षा की दृष्टि से चौराहे का त्वरित सुधार आवश्यक है। शास्त्री चौक पर फुटपाथ और सड़क के बीच बनी दीवार को शहर की सुंदरता और यातायात सुगमता के लिए बाधक बताते हुए उसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की।

चोरी की बाइक के साथ युवक गिरफ्तार

बस्ती। लालगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रविवार रात चोरी की बाइक के साथ युवक को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय भेज दिया। एसएचओ संजय कुमार ने बताया कि रात करीब 9 बजे सूचना मिली कि बरम बाबा मॉंदर परिसर, बासापार में एक युवक चोरी की बाइक के साथ मौजूद है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबाच लिया। पृष्ठताछ में आरोपी की पहचान थाना लालगंज के गोनार निवासी उमेश यादव पुत्र भागीरथी यादव (30) के रूप में हुई।

सम्पादकीय

देश को फिर गुलाम बनाने की तैयारी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करीबी माने जाने वाले कारोबारी गौतम अडानी को बिहार में बिजली संयंत्र लगाने का बड़ा ठेका मिला है। कंग्रेस का आरोप है कि बजट में भाजपा ने घोषणा की थी कि इस संयंत्र को सरकार लगाएगी, लेकिन अब ठेका, संयंत्र लगाने के लिए जमीन और बिजली बेचने का अधिकार सब अडानी समूह को दिया गया है। सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। देश को निजीकरण की जंजीरों में किस तरह जकड़ा जा रहा है, यह उसका ताजा उदाहरण है। जब भारत की प्राकृतिक संपदा और आर्थिक समृद्धि को देखकर अंग्रेज व्यापार करने आए थे, तब ईस्ट इंडिया कंपनी की लुभावनी बातों और आकर्षक सौदों में फंसकर राजाओं ने उन्हें मनमाने नियमों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी। बदले में राजाओं को सैन्य मदद या किसी और किस्म का निजी लाभ मिल जाया करता था। इन सौदों में प्रजा के हितों के लिए कोई जगह नहीं थी। जिस प्रजा से तरह-तरह के कर वसूले जाते थे, उसके बारे में न राजाओं ने न ईस्ट इ़ंडिया कंपनी ने कुछ सोचा। नतीजा देश की दो सौ साल की गुलामी के रूप में सामने आया। तब की प्रजा आजाद भारत में नागरिक बन गई, उसे सरकार चुनने का हक देकर शक्ति संपन्न किया गया। लेकिन मौजूदा सरकार ईस्ट इ़ंडिया काल की तरह ही अभी फिर से जनता को प्रजा बनाने में लगी है, ताकि आज के व्यापारियों को मनमाने लाभ कमाने की हूट मिले। देश में अब जो बची-खुची प्राकृतिक संपदा रह गई है, उसे भी हड़प कर भारत को नवी गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। अडानी समूह ने एनडीए शासित बिहार में राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) के साथ 25 साल के बिजली आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भागलपुर जिले के पीरपैंती में बनने वाले बिजली संयंत्र से राज्य को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। पीरपैंती आने वाले वक्त में बिहार का ऊर्जा हब बन जाएगा, ऐसा कंपनी का दावा है। अडानी समूह के मुताबिक इस परियोजना में लगभग तीन अरब डॉलर (26,482 करोड़ रुपये) का निवेश होगा और इससे कम से कम 12 हजार लोगों के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगले पांच साल में संयंत्र काम करने लग जाएगा, ऐसा कंपनी का अनुमान है। मतलब अगले चुनाव पर फिर इस संकंत्र के आधार पर वोट मांगने की तैयारी होगी। क्योंकि अभी नरेन्द्र मोदी ने इस का शिलान्यास किया है, अगले चुनाव में वे कहेंगे कि बिजली उपलब्धता के लिए हमें वोट दीजिए। जिस काम को करना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए, जो उसकी जिम्मेदारी है और जनता का बुनियादी हक है, उसे चुनावी मुद्दा भाजपा ने बनाया है। अडानी समूह की तरफ से बिजली आपूर्ति, उद्योगों को लाभ, रोजगार के मौके जैसी बातें कही जा रही हैं, जो बताता है कि विकास की चकाचौंध में कैसे जनता को गुमराह किया जाता है। अडानी समूह अगर करोड़ों का निवेश कर बिजली संयंत्र लगा सकता है और इतना बिजली उत्पादन कर सकता है कि बिहार का विकास हो जाए, तो इसी काम को करने से सरकार को किसने रोका है। जब नीतीश कुमार 20 सालों से सत्ता में हैं और नरेन्द्र मोदी 11 सालों से केंद्र में हैं, तब भी दोनों मिलकर बिहार के लिए एक बिजली संयंत्र नहीं लगा सके, क्या इसे एनडीए सरकार की बड़ी विफलता के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन भाजपा और उसका मीडिया दोनों इसे बड़ी उपलब्धि बताते में लगे हैं। गौरतलब है कि अगस्त महीने में उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अडानी पावर को स्वीकृति पत्र जारी किया था। अडानी पावर ने 6 रुपये 75 पैसे प्रति किलोवाट घंटा की न्यूनतम दर की पेशकश कर यह अनुबंध हासिल किया। समझौते के अनुसार, प्लांट से उत्पादित बिजली सीधे बिहार की वितरण कंपनियों तक पहुंचेगी, जिससे राज्य की बिजली स्थिति में सुधार होगा।। कहा जा रहा है कि यदि यह परियोजना समय पर पूरी होती है, तो यह न केवल ऊर्जा आपूर्ति को गारंटी देगी बल्कि बिहार में औद्योगिक माहौल को भी बेहतर करेगी। इस निवेश से प्रदेश की छवि एक शिववेश-अनुकूल राज्य के रूप में बन सकती है। ऐसे ही लुभावने सपने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी उस समय के राजाओं को दिखाए थे, जो आखिर में ये तक मानने लगे थे कि अंग्रेज हैं तो उनका उद्धार होगा, वर्रां वे अपने दम पर कुछ कर ही नहीं सकते। जिन राजाओं ने ऐसा नहीं माना, उनकी न केवल सत्ता छीनी गई बल्कि मौत के घाट भी उतारा गया दुःखद है कि देश को एक बार फिर गुलामी की राह पर चलने के लिए मोदी सरकार मजबूर कर रही है। बताया जा रहा है कि भागलपुर में जो 1020 एकड़ जमीन 30 साल की लीज पर अडानी समूह को दी गई है, वो एक रूपए में दी गई है। जमीन को बंजर बताया गया है, जबकि वहां आम और लीची के पेड़ लगे हैं, संयंत्र लगाने के लिए कम से कम 10 लाख आम के पेड़ काटे जाएँी, ऐसी खबर भी आई है।

भारत : घृणारूपद भाषण और राजनीति का बढ़ता चक्र

राम पुनियांनी
साम्प्रदायिक हिंसा भारतीय राजनीति का अभिशाप रही है। यह साम्प्रदायिक राजनीति का आधार भी बनती है जिसका उद्देश्य समाज को धर्म के

दोहराया जाता रहा। विभाजन-पूर्व हिंसा की गतिशीलता बहुत अलग थी और दोनों समुदाय समान रूप से इसमें शामिल थे। विभाजन के बाद, मुस्लिम साम्प्रदायिकता के प्रमुख तत्वों के पाकिस्तान चले जाने



आधार पर चँँटना है। इस नफरत की नींव अंग्रेजों ने रखी, जिन्होंने शफूट डालो और राज करोश की नीति अपनाई। शुरुआत में, इतिहास के साम्प्रदायिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके ऐसा किया गया। इसे एक तरफ मुस्लिम लोग और दूसरी तरफ हिंदू महासभा-आरएसएस ने समानांतर और विपरीत दिशाओं में विकसित किया। इससे साम्प्रदायिक हिंसा की उत्पत्ति और विकास हुआ। इतिहास में धीरे-धीरे अन्य भावनात्मक मुद्दे जुड़ते गए और शूद्रसेस समुदाय के प्रति नफरत बढ़ती गई। हिंसा बढ़ने लगी, जिससे विभाजन-पूर्व जैसी भावावह हिंसा हुई। विभाजन की त्रासदी के बाद यह शूद्रसों से नफरतश् का चक्र नियमित रूप से

के साथ, हिंसा मुख्य रूप से मुस्लिम-विरोधी हिंसा में बदल गई। मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत धीरे-धीरे बढ़ने लगी और सामाजिक चेतना में और गहरी जड़ें जमाती चली गई। आरएसएस की शाखाओं में महान हिंदू राजाओं और दुष्ट मुस्लिम राजाओं की कहानियों के जरिए पैदा की जाने वाली नफरत, और उसके द्वारा संचालित स्कूलों और मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली नफरत, 1977 के बाद और भी बड़ गई, जब सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी ने यह सुनिश्चित किया कि समाचार एजेंसियों में साम्प्रदायिक मानसिकता वाले लोग चुमाएँ पैसे करें। मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही, मोदी के करीबी कॅॉर्पोरेट

विचार

इतिहास का विराट व्यक्तित्व, जिसने बदल दिया राष्ट्र का स्वरूप

अक्टूबर 2001 का पहला सप्ताह....दिल्ली की फिजाओं में शाम के वक्त गुलाबी सर्दी ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी...संसद से कुछ ही दूरी पर स्थित रफी मार्ग की आईएनएस बिल्डिंग के सामने संजय की चाय का टीया रोजाना की तरह गुलजार था..देशभर के अखबारों और टीवी चैनलों के रिपोर्टरों की शाम की चाय की चुस्कियों के साथ यहीं गुजरती थी...इन चुस्कियों के बीच से ही खबरेँ भी छनकर आती थीं...इसी बीच बीजेपी कवर करने वाला एक पत्रकार सड़क पारकर आता दिखा..आते ही उसने पहले से उपस्थित लोगों के सामने एक प्रश्न उछाल दिया, मुंह बिचकाने और इसे असंभव मानने वाले पत्रकारों की भी सोच अपनी जगह सही थी...नरेंद्र मोदी उन दिनों भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भले ही थे, लेकिन उनके पास ना तो चुनाव लड़ने का अनुभव था, ना ही कभी किसी प्रशासनिक पद को संभालने का...तब तक की राजनीति के लिहाज से किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए ये प्राथमिक योग्यताएँ होती थीं... नरेंद्र मोदी का चयन कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था...तब गुजरात भाजपा तत्कालीन मुख्यमंत्री केशु भाई पटेल और शंकर सिंह बाधेला खेमे के बीच बंटी हुई थी। राज्य बीजेपी में पांच साल पहले गुटबाजी के चलते जो हुआ था, वह राजनीति की दुनिया की शर्मनाक घटनाओं में शुमार है..तेरह दिनी सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान समारोह में जो हुआ, वह इतिहास हो चुका है... गुजरात में बीजेपी की सरकार तो थी, कुछ महीने पहले पड़े अकाल के चलते राहत कार्यों के लेकर हलकान थी। अगर संगठन में एकता होती तो सरकार अपना सारा ध्यान अकाल राहत पर होता, लेकिन गुटबाजी के चलते ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था..राज्य बीजेपी का समर्थक पटेल खेमा अपने नेता के साथ खड़ा था तो क्षत्रिय समेत दूसरी जातियाँ महेले के साथ। ऐसे में सरकार का प्रदर्शन हिचकोले तो खा ही रहा था, बीजेपी की संभावनाएँ भी कमजोर हो रही थीं... ऐसे माहौल में बीजेपी के आलाकमान का ध्यान संघ के प्रचारक रहे गुजराती मूल के नरेंद्र मोदी की ओर गया। अटल जी के दफ्तर ने जब उन्हें फोन कर के प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचने के संदेश दिया, तब आज की तरह मोबाइल ज्यादा नहीं होते थे..तब मोदी दिल्ली के निगम बोध घाट पर संसद हमले में घायल कैमरामैन के निधन के बाद उसके अलेंगिष्ठ में शामिल थे। एक राष्ट्रीय चैनल के उस कैमरामैन के शोक संतप परिवार को धीरज बंधा रहे मोदी के पास फेने आया और उनकी जिंदगी ही बदल गई। नरेंद्र

मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 के दिन गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अभी वे प्रशासन को समझ ही रहे थे, सूखा ग्रस्त गुजरात के लोगों और किसानों के राहत के लिए प्रयासरत ही थे, कि प्रकृति ने उनकी बड़ी परीक्षा ले ली। 26 जनवरी 2002 के दिन कच्छ में जबरदस्त भूकंप आया। इस भूकंप में जान-मान की व्यापक क्षति हुई। गुजरात जैसे हिलत गया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे चुनौती की तरह लिया। गुजरात के नवनिर्माण का उन्होंने संकल्प लिया। भीगी आंखों वाले कच्छ के आंसुओं को पोछ, और देखते ही देखते अपने कुशल नेतृत्व और सूझबूझ के साथ गुजरात को देश के प्रतिष्ठित राज्यों में स्थापित कर दिया। भारत को आजादी देते वक्त ब्रिटिश सरकार को कई कार्रदों को उम्मीद थी कि भारत जल्द ही बिखर जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तो मानते थे कि भारत की आजादी देर तक नहीं टिकेगी। लेकिन भारत ने अपना संविधान तैयार किया। संविधान ने पहले ही रूखाव से व्यवस्क और बराबरी का मतदान अधिकार दिया। स्त्री-पुरूष, ऊंच-नीच, जाति, धर्म का कोई भेद नहीं रखा। इसी संविधान की बुनियाद पर देश आगे बढ़ता रहा। इसी संविधान की ही सफलता है कि गुजरात के वडनगर के एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में जन्मा बच्चा आज भारतीय लोकतंत्र के शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री मोदी की जीवन यात्रा जहां उनके उत्कट देशे्प्रेम और राष्ट्रनिष्ठा का उदाहरण है। उन्होंने ज़िंदगी कठोर परिश्रम एवं अध्यवसाय का भी प्रतीक है। जिस उम्र में आम नौजवान ज़िंदगी संवारेन की कोशिश करता है, देश और समाज के लिए नरेंद्र मोदी ने उस उम्र में घर छोड़ दिया...इसकी प्रेरणा उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिली, जिससे उनका स्कूली दिनों से ही संपर्क रहा। 17 सितंबर 1957 को गुजरात के वडनगर में जन्मे मोदी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 8 साल की उम्र में जुड़ गए और स्थानीय शाखा में जाने लगे। मोदी 1960 के दशक के अंत में संघ से स्थायी रूप से जुड़े और घर-परिवार छोड़कर अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में स्थित संघ के कार्यालय हेडोवार् भवन में रहने चले गए। इस दौरान उन्हें गुजरात के

तब से लेकर 1985 तक उन्होंने प्रचारक के तौर पर गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बुनियाद मजबूत करने की भूमिका निभाई। इसके अगले साल, राज्य में गुजरात नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था। छात्रों द्वारा शुरू में शामिल हो गए। यह आंदोलन गुजरात में छात्रों द्वारा शुरू किया गया था। सुरेंद्रनगर से शुरू इस आंदोलन का मकसद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ था। प्रचारक रहते मोदी को संघ ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने के लिए भेजा गया। देखते ही देखते यह आंदोलन बिहार तक पहुंच गया। बिहार के छात्रों और नौजवानों ने जयप्रकाश नारायण की अगुआई में आंदोलन छेड़ दिया। देखते ही देखते यह आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया। जयप्रकाश नारायण की अगुआई में चल रहे इस आंदोलन को भारतीय इतिहास में बिहार छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के ही दौरान इंदिरा गांधी की रायबरेली से निर्वाचन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इसी छाया में 25 जून 1975 की आधी रात को इंदिरा सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया।

ईपीएफ सेवाएं भी उपभोक्ता आयोग के दायरे में

सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे में माना है। कोई भी कर्मचारी भले ही वह सेवानिवृत्त हो गया हो, ईपीएफओ की सेवाओं में कमी या सेवाओं में देरी जैसे मामलों के लिए उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। पीएफ राशि जमा न होना, पेंशन राशि न मिलना, या पीएफ निकासी में देरी जैसे मामलों में उपभोक्ता अदालत से न्याय प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि यानि ईपीएफ से संबंधित समस्याओं के लिए कर्मचारी उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटा सकता हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे में माना है। कोई भी कर्मचारी भले ही वह सेवानिवृत्त हो गया हो, ईपीएफओ की सेवाओं में कमी या सेवाओं में देरी जैसे मामलों के लिए उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। पीएफ राशि जमा न होना, पेंशन राशि न मिलना, या पीएफ निकासी में देरी जैसे मामलों में उपभोक्ता अदालत से आसानी से न्याय प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि यानि ईपीएफ योजना की स्थापना सन-1952 में भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति बचत योजना प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रबंधित इस योजना में कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों की ओर से एक निश्चित राशि का योगदान अनिवार्य है, जिसका उपयोग सेवानिवृत्ति, नौकरी परिवर्तन या जीवन की विशिष्ट घटनाओं जैसे चिकित्सा आपात स्थिति या घर खरीदने पर किया जा सकता

है। ईपीएफ का उद्देश्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवन में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना में संचित धनराशि पर ब्याज मिलता है और सेवानिवृत्त होने के समय तक यह एक बड़ी राशि जमा हो जाती है। कर्मचारियों द्वारा अपनी नौकरी बदलने पर कर्मचारी के ईपीएफ खातों से धनराशि के हस्तांतरण में देरी, धनराशि निकालने में कठिनाई और खाते की शेष राशि में विसंगतियां व समस्याएं आती हैं। वही ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों और धीमे प्रसंस्करण समय सहित समस्याओं का आना भी आम बात है। इन परिचालन चुनौतियों ने कर्मचारी सदस्यों में निराशा पैदा की है, जिसके कारण ईपीएफओ को अनुभव और दक्षता में सुधार के लिए अपने सिस्टम और ग्राहक सेवा प्रोटोकॉल को लगातार अपडेट करना पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने गत 16 जुलाई, 2025 तक उच्च पेंशन लाभ के लिए 15.24 लाख आवेदनों में से 98.5 फीसदी का निपटान कर दिया है। जिनमें केवल 4,00,573 आवेदनों को ही स्वीकृत किया गया और मांग पत्र भेजे गए हैं, वहीं, 21,995 आवेदन अभी भी समीक्षाधीन हैं। चेन्नई और पुडुचेरी क्षेत्र में अस्वीकृति दर सबसे अधिक रही। यह मुद्दा 2014 के एक सर्कुलर से उपजा है, जिसमें उच्च पेंशन लाभों को केवल एक निश्चित वेतन सीमा से ऊपर कमाने वालों तक सीमित कर दिया गया था। हालांकि, नवंबर 2022 के अपने फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 1 सितंबर, 2014 से पहले पंजीकृत ईपीएफ सदस्य, जो या तो अभी भी कार्यरत

हैं या उस तिथि के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, वे वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन के पात्र हैं, न कि निर्धारित सीमा के आधार पर। कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना को वैध ठहराया है। हालांकि कोर्ट ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया है। बता दें कि 2014 के इस संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर) की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की थी। जबकि संशोधन से पहले, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2014 कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना को वैध ठहराया है. हालांकि पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया। बता दें कि साल 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर) की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की थी जबकि पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था। आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें छह महीने के भीतर ऐसा करना होगा। पात्र कर्मचारी जो अंतिम तारीख तक योजना में शामिल नहीं हो सके, उन्हें एक अतिरिक्त मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने सन 2014 की योजना में इस शर्त को अमान्य करार दिया कि कर्मचारियों को 15,000 रुपये से अधिक के वेतन पर 1.16 प्रतिशत का अतिरिक्त योगदान देना होगा। स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों को राहत मिली है और भविष्य में भी न्याय के लिए उनके लिए उपभोक्ता अदालत के दरवाजे खुले हैं।

प्रदूषण के पटाखे

भारत जैसा देश, जो दुनिया भर के प्रदूषित देशों में पांचवें नंबर पर हो, जहां दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हो और तेरह अन्य शहर दुनिया के शीर्ष बीस प्रदूषित शहरों में शुमार हों, वहां हवा को जहरीला बनाने वाले पटाखे निरंकुश रूप से जलाना एक आत्मघाती कदम ही है। लेकिन विडंबना यह कि इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा केवल दिल्ली के प्रदूषण और पटाखों पर अंकुश लागों को लेकर होती है। इस स्थिति में दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर अंकुश लगाने के संदर्भ में देश की शीर्ष अदालत की टिप्पणी संवेदनशील और मार्गदर्शक है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि यदि साफ वायु राष्ट्रीय राजधानी के विशिष्ट लोगों का हक है तो यह हक शेष देश के हर व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। वैसे तो राष्ट्रीय राजधानी में वायु दूषित होने के तमाम कारक हैं,लेकिन पटाखों से होने वाले प्रदूषण की चर्चा गाहे-बगाहे होती है। खासकर कुछ प्रमुख त्योहारों के मौके व निजी समारोहों में जलाये जाने वाले पटाखों को लेकर लगातार सवाल उठाये जाते हैं। इसकी वजह यह है कि यह प्रदूषण का ऐसा कारण है जिससे बचा जा सकता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि दिवाली आदि के मौके पर हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट देखी जाती है। सवाल यह है कि हम लोग क्यों नहीं सोचते कि हमारे पटाखे

जलाने से श्वास रोगों से जूझते तमाम लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। यह एक हकीकत है कि देश के तमाम शहरों में हवा ही नहीं, पानी व मिट्टी तक में जहरीले तत्वों का समावेश हो चुका है। जो न केवल हमारी आबोहवा के लिये बल्कि हमारे शरीर के लिये भी घातक साबित हो रहा है। यही वजह है कि हाल के वर्षों में देश में श्वसन तंत्र से जुड़े रोगों में अत्रत्याशित वृद्धि हुई है। साथ ही प्रदुषित हवा के प्रभाव में सांस संबंधी रोगों से लोगों के मरने का आंकड़ा भी बढ़ा है। कहीं न कहीं हमारे वातावरण में बढ़ता प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाले कारकों में वृद्धि भी कर रहा है। लेकिन पटाखों से होने वाला प्रदूषण ऐसा है जो हमारे संयम के जरिये रोका जा सकता है।चिंता की बात यह है कि पटाखों के जलने से निकलने वाले कण हमारे श्वसनतंत्र को नुकसान पहुंचाने के साथ ही हमारे खून में घुल रहे हैं। जिसमें पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे महीन कण फेफड़ों में प्रवेश करके गंभीर रोगों को जन्म दे रहे हैं। इतना ही नहीं पटाखे जलाने के कारण जहरीली रासायानिक गैसों के रिसाव से हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र को गंभीर क्षति पहुंच रही है। साथ ही ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी हमारे वायुमंडल में जलवायु परिवर्तन के संकटों को बढ़ाने में भूमिका निभा रहा है। लेकिन हम इसके बावजूद निजी सुख के लिये

दूसरों के जीवन से खिलवाड़ से परहेज नहीं करते। सही मायनों में असली खुशी वही होती है जिससे हमारा समाज सुखी, स्वस्थ और खुश रह सके। अब चाहे हमारे त्योहार हों या निजी उत्सव, वे समाज के लिये अहितकारी नहीं होने चाहिए। देर-सेवर इस संकट की कीमत हर नागरिक को चुकानी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के आलोक में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अब चाहे दुनिया का सबसे प्रदुषित शहर बनीहाट हो या पंजाब व राजस्थान के सबसे अधिक प्रदूषित शहर हों, उन्हें भी पटाखों के नियमन का लाभ मिलना चाहिए। यही वजह है कि अदालत को कहना पड़ा कि साफ हवा देश के हर नागरिक का अधिकार है। ऐसे में हमें दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की चिंता के साथ ही शेष देश की भी चिंता गंभीरता से करनी चाहिए। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि दिल्ली में पटाखों पर नियंत्रण का जो भी फायदा बने, उसे सारे देश में भी लागू करना चाहिए। यह संकट सारे देश का है। एक नागरिक के तौर पर हमारा जिम्मेदार व संवेदनशील व्यवहार ही हमें इस संकट से उबार सकता है। विगत में सख्त कानून लागू करने के बावजूद नागरिकों के गैर-जिम्मेदार व्यवहार से प्रदूषण का संकट बढ़ा ही है।



महिला वनडे विश्व कप से पहले टीम इंडिया को मिला बड़ा बूस्ट, स्मृति मंधाना बनीं नंबर एक बल्लेबाज

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना वनडे में फिर से नंबर एक बल्लेबाज बन गई हैं। आईसीसी की ताजा महिला वनडे रैंकिंग में उन्होंने फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया। यह उपलब्धि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में अर्धशतक जड़ने के बाद मिली। मुल्तापुर में खेले गए तीन मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में मंधाना ने 63 गेंदों में 58 रन बनाए, लेकिन उनका यह प्रयास बेकार गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से लक्ष्य का पीछा कर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। वर्ल्ड कप से पहले बड़ा बूस्ट नंबर एक रैंकिंग 30 सितंबर से शुरू होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप से पहले मंधाना के आत्मविश्वास को बढ़ावा देगी। इस अर्धशतक से उन्हें सात रेटिंग प्वाइंट्स मिले और वे इंग्लैंड की नेट स्किवर-बंट से चार अंक आगे निकल गईं, जो अब दूसरे स्थान पर हैं।

नाॅमिनेशन में हुआ बड़ा 'खेला', इन 5 कंटेस्टेंट्स पर लटकी बेघर होने की तलवार



रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में इस बार नाॅमिनेशन की प्रक्रिया में बड़ा ट्विस्ट आया। इस हफ्ते आखिर किस-किस कंटेस्टेंट पर एंक्वशन की तलवार लटकी है, चलिए जानते हैं। टीवी की दुनिया का सबसे चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' हमेशा से ही दर्शकों के लिए ड्रामा, इमोशन और सरप्राइज लेकर आता है। सलमान खान के होस्टिंग वाले इस शो में हर हफ्ते नाॅमिनेशन का दौर

दिलचस्प होता है। इस बार भी घर के अंदर ऐसा ही हुआ जब नाॅमिनेशन प्रक्रिया में बिग बॉस ने एक ऐसा दांव खेला, जिसने सभी प्रतिযোগियों के होश उड़ा दिए। शो का माहौल पूरी तरह बदल गया और अंत में पांच कंटेस्टेंट्स पर बेघर होने की तलवार लटक गई। नाॅमिनेशन का खेल शुरू घर के अंदर जब नाॅमिनेशन का एलान हुआ तो सभी सदस्यों को एक साथ बुलाया गया और उनसे दो-दो नाम मांगे गए

जिन्हें इस हफ्ते वो बेघर होने से बचाना चाहते हैं। हर किसी ने अपनी रणनीति के मुताबिक प्रतिद्वंदियों को नाॅमिनेट किया। किसी ने दोस्ती निभाई तो किसी ने पुरानी दुश्मनी का हिसाब चुकता करने का मौका ढूँढ़ा। कभी शांत रहने वाले कंटेस्टेंट्स भी इस प्रक्रिया में आक्रामक दिखे। किसी ने गठबंधन की राजनीति खेली तो कोई बिल्कुल अकेला खड़ा नजर आया। इस बीच

कई नाम ऐसे सामने आए जिनसे फैन्स भी चौंक गए। बिग बॉस का मास्टरस्ट्रोक जैसे ही घरवाले सोच रहे थे कि नाॅमिनेशन का दौर सामान्य तरीके से खत्म हो जाएगा, तभी बिग बॉस ने माहौल पलट दिया। उन्होंने घरवालों को अमाल और नीलम की बातचीत का एक ऑडियो सुनाया, जिसमें दोनों नाॅमिनेशन पर चर्चा करते पकड़े गए थे। यह नियमों के खिलाफ था। इस पर बिग बॉस ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि जब घर के सदस्य प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लेते, तो परिणाम भी उन्हें झेलना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने पूरे घर को नाॅमिनेट करने का बड़ा ऐलान कर दिया। कंटेस्टेंट्स ने एक दूसरे को किया सेव हालांकि यहीं खेल खत्म नहीं हुआ। बिग बॉस ने ट्विस्ट डालते हुए सभी को एक और मौका दिया। नियम यह बना कि हर प्रतियोगी को दो ऐसे सदस्यों के नाम बताने होंगे जिन्हें वो सुरक्षित करना

चाहते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिनके नाम सबसे कम बार लिए गए, वे नाॅमिनेशन की लिस्ट में चले गए। कौन-कौन हुआ नाॅमिनशन का शिकार? सभी वोटिंग और चर्चाओं के बाद आखिरकार पांच नाम ऐसे सामने आए जिनके लिए यह हफ्ता बेहद मुश्किल साबित होने वाला है। ये सदस्य हैं – अशनूर कौर, बसीर अली, अभिषेक बजाज, नेहल चुडासमा और प्रणित मोरे। इन पांचों को अब दर्शकों के वोट का इंतजार रहेगा। शो में आया रोमांच इस पूरे घटनाक्रम ने बिग बॉस 19 के घर का माहौल पूरी तरह बदल दिया है। जहां एक ओर प्रतियोगी अपनी-अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दर्शक भी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर आने वाले वीकेंड पर सलमान खान किसका टिकट काटेंगे। सोशल मीडिया पर इन नाॅमिनेशन्स को लेकर चर्चा जोरों पर है और फैन्स अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को बचाने की मुहिम में जुट गए हैं।

अमाल मलिक पर भड़कीं गौहर खान, कुनिका का किया जिक्र; बोलीं-थोड़ा तो ख्याल करो



बिग बॉस 19 इन दिनों काफी चर्चाओं में है। हाल ही में शो में अमाल मलिक और कुनिका सदानंद के बीच बहस हो गई थी। अब इस मामले पर एक्ट्रेस गौहर खान ने अमाल की आलोचना की है। पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 के घर में आए दिन किसी ना किसी प्रतियोगियों के बीच झड़प और कहासुनी होती रहती है। हाल ही में शो में दिखा कि अमाल मलिक और कुनिका सदानंद के बीच गहमागहमी हो गई थी। इसी मामले पर बिग बॉस 7 की विजेता और अभिनेत्री गौहर

खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अमाल पर हमला बोला है। जानिए उन्होंने क्या कहा। थोड़ा तो ख्याल करो... गौहर खान ने अपने एक्स अकाउंट पर एक टवीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, ह्यूहॉ, वो बहुत नखरे बाज, अपने फैसलों को लेकर चिड़चिड़ी हैं। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि ज्यादातर लोग कुनिका जी से कैसे बात करते हैं। वो 61 साल की हैं यार, थोड़ा तो ख्याल रखो टोन का। बिग बॉस 19 में अमाल जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते।

अधिकार का पद जिम्मेदारी के साथ आता है। किस बात पर भिड़े थे अमाल-कुनिका? इस समय बिग बॉस 19 में अमाल मलिक कै प्टन हैं। पिछले एपिसोड में अमाल और कुनिका सदानंद के बीच किचन के कामों को लेकर बहस हो गई थी। अमाल ने कुनिका को एक तरफ हट जाने और दूसरों को किचन संभालने देने को कहा, जिसके बाद दोनों के बीच बहस छिड़ गई। बाद में शो की प्रतियोगियों तान्या और नीलम ने कहा कि कुनिका अक्सर किसी के बीच में शामिल हो जाती हैं।

उर्वशी रौतेला के बाद अवैध बेटिंग एप मामले में आया सोनू सूद का नाम, ईडी ने पूछताछ के लिए भेजा समन



बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी और असल जिंदगी में गरीबों के मसीहा कहलाने वाले सोनू इस बार एक गंभीर मामले के कारण चर्चा में आए हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, पूर्व सांसद मिमि चक्रवर्ती, पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और युवराज सिंह के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (एन) ने एक्टर सोनू सूद को गैरकानूनी बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। सोनू सूद अवैध ऑनलाइन बेटिंग ऐप को लेकर ईडी के सवालों के घेरे में आ गए हैं। कब और क्यों बुलाए गए सोनू सूद? ईडी ने सोनू सूद को

24 सितंबर को दिल्ली स्थित मुख्यालय में पेश होने का आदेश दिया है। एजेंसी का मानना है कि उन्होंने एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ प्रमोशनल जुड़ाव किया, जो भारत में बैन हैं। यह एप कथित तौर पर अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और पैसों की हेराफेरी में शामिल है। जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों की ब्रांडिंग से इस एप को किस हद तक फायदा हुआ और क्या इससे जुड़े भुगतान नियमों का उल्लंघन हुआ। ईडी की जांच का दायरा प्रवर्तन निदेशालय लंबे समय से इंटरनेट पर चल रही ऐसी बेटिंग वेबसाइट्स पर नजर रख रहा है, जो भारत के

कानून के खिलाफ हैं। इन प्लेटफॉर्म के जरिए न सिर्फ सट्टेबाजी होती है बल्कि हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों की भी आशंका जताई जा रही है। अब जब इन मामलों में फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों के नाम सामने आ रहे हैं, तो जांच का दायरा और भी बढ़ गया है। उर्वशी रौतेला को भी बुलाया गया जानकारी के मुताबिक मिमि चक्रवर्ती को 15 सितंबर और उर्वशी रौतेला को 16 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए गए हैं। जांच एजेंसी ये समझना चाहती है कि आखिर इन सितारों की भूमिका इन एप्स के प्रचार और पब्लिसिटी में किस हद तक रही है।

आलोक नाथ को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, हरियाणा मार्केटिंग घोटाले में गिरफ्तारी पर रोक

अभिनेता आलोक नाथ को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। हरियाणा मार्केटिंग स्कैम मामले में आलोक की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। बॉलीवुड के ह्यसंस्कारी बाबूजीहू के नाम से पहचाने जाने वाले चर्चित अभिनेता आलोक नाथ इन दिनों एक बड़े विवाद में फंसे हुए हैं। हरियाणा में दर्ज एक कथित मार्केटिंग फ्रॉड केस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। हालांकि, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला? मामला हरियाणा की एक मल्टी मार्केटिंग कंपनी और उससे जुड़े ह्यूमन वेल्फेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का है। यह सोसाइटी सितंबर 2016 से सक्रिय थी और कई राज्यों में अपनी शाखाएं खोल चुकी थी। संस्था ने जनता को आकर्षित करने के लिए फिक्सड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट जैसी बचत योजनाओं की पेशकश की और निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा

और समय पर उन्हें बेहतर रिटर्न मिलेगा। शुरूआती कुछ वर्षों तक भुगतान होता भी रहा, जिससे लोगों का विश्वास और गहरा गया। लेकिन शिकायत के अनुसार, साल 2023 में अचानक निवेशकों को परिपक्वता राशि (मच्योरिटी अमाउंट) मिलना बंद हो गया। सोसाइटी के अधिकारियों ने देरी को ह्यसिस्टम अपग्रेडेशनहू का बहाना बनाकर टालना शुरू किया और धीरे-धीरे निवेशकों से पूरी तरह संपर्क तोड़ दिया। अभिनेता क्यों फंसे मामले में? इस धोखाधड़ी में 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें अभिनेता आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े भी शामिल हैं। शिकायतकर्ता विपुल अंतिल का आरोप है कि दोनों अभिनेताओं ने इस सोसाइटी का बतौर बांड एग्जैसेडर प्रचार किया था। उनका कहना है कि जब मशहूर हस्तियों ने इस संस्था का प्रचार किया तो लोगों ने इसे भरोसेमंद मानकर निवेश किया। पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है और यह पता लगाया जाएगा कि इन दोनों सितारों की इसमें



कितनी गहरी भूमिका रही। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही मंगलवार को न्यायमूर्ति बी.वी. नागरबा और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने हरियाणा पुलिस और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया और कहा कि अगली सुनवाई तक आलोक नाथ के खिलाफ कोई भी कठोर कदम न उठाया जाए। इससे पहले इसी मामले में अभिनेता श्रेयस तलपड़े को भी शीर्ष अदालत से राहत मिल चुकी है। मामले की शिकायत

और कानूनी धाराएं एफआईआर 22 जनवरी 2024 को दर्ज की गई थी। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316(2), 318(2) और 318(4) के तहत गंभीर अपराधों का जिक्र है, जिनमें आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी प्रमुख हैं। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि यह सोसाइटी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल पर काम करती थी। शुरूआती रिटर्न देकर उसने निवेशकों का विश्वास जीता और बाद में

लाखों रुपये हड़प लिए। गिरफ्तारी पर लगी रोक फिलहाल आलोक नाथ को गिरफ्तारी से सुरक्षा मिल गई है, लेकिन जांच जारी है। कोर्ट के अगले आदेश तक उनकी भूमिका और जिम्मेदारी की तहकीकात होगी। अगर यह साबित होता है कि उन्होंने केवल प्रचार किया और धोखाधड़ी से अनजान थे, तो उन्हें राहत मिल सकती है। लेकिन अगर उनके खिलाफ ठोस सबूत मिले तो मामला उनके लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है।

अफवाहों ने उनकी जिंदगी में गड़बड़ कर दी, संग्राम सिंह से अफेयर पर निकिता रावल ने तोड़ी चुप्पी



अभिनेत्री पायल रोहतगी और संग्राम सिंह की शादी को लेकर इन दिनों तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि संग्राम का एक्सट्र मैरिटल अफेयर चल रहा है। अब इस पर निकिता ने चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में कुश्ती से फिट्स इंडस्ट्री में कदम रखने वाले संग्राम सिंह और अभिनेत्री पायल रोहतगी की शादी को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। खबरें आ रही हैं कि संग्राम सिंह का अभिनेत्री निकिता रावल के साथ

एक्सट्र मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिससे चर्चा बढ़ गई है। लेकिन जब डिजिटल निकिता रावल से इस बारे में बात की तो उन्होंने इन अफवाहों को पूरी तरह नकार दिया। संग्राम मेरे अच्छे दोस्त से बातचीत में निकिता ने साफ कहा, 'संग्राम मेरे अच्छे दोस्त हैं और ये गलत खबरें पहले ही उनके निजी जीवन में बहुत गड़बड़ कर चुकी हैं। मैं इन अफवाहों से बहुत परेशान हूं। लेकिन मैं इस बारे में आगे बात नहीं करना चाहती क्योंकि यह एक

निजी मामला है।' जल्द ही बयान जारी कर सकते हैं संग्राम ये सब उस समय सामने आया है जब संग्राम सिंह और पायल रोहतगी करिश्ते को लेकर पहले से ही कई तरह की खबरें आ रही हैं, जिसमें अलगाव और मनमुटाव की बातें भी शामिल हैं। फिलहाल तो न तो संग्राम और न ही पायल ने इन अफवाहों पर खुलकर बात की है। माना जा रहा है कि संग्राम इस मुद्दे पर बहुत जल्द कोई आधिकारिक बयान जारी कर सकते

हैं। पहले संग्राम ने किया था अफवाहों को खारिज इससे पहले भी संग्राम और पायल के तलाक की खबरें सामने आ चुकी है। हालांकि संग्राम ने उस समय इन अफवाहों का खंडन किया था। डिजिटल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने पायल से अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बातचीत की थी। तब डिजिटल से बातचीत में संग्राम ने कहा था, 'अगर पायल की बात करें, तो लगभग 14 साल हो गए हमारे साथ की। लोग अक्सर अटकलें लगाते हैं कि चीजें

सही नहीं चल रही, लेकिन जब हम साथ में कुछ पोस्ट करते हैं या कोई इंटरव्यू आता है, तो लोग समझ जाते हैं कि सब ठीक है। हमारे रिश्ते में भी आम कपल्स जैसी खटपट होती है - कभी झगड़ा, कभी बहस, कभी समझदारी।' पहले मैं उसे बेवकूफ समझता था, अब शायद वो मुझे तब संग्राम ने आगे कहा था कि दरअसल, पायल और मैं बिल्कुल अलग सोच रखते हैं।

